



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, सोमवार, 16 अप्रैल, 2001/26 चैत्र, 1923

---

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 16 अप्रैल, 2001

संख्या 1-28/2001-वि० स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत "हिमाचल प्रदेश पथकर (संशोधन) विधेयक, 2001 (2001 का विधेयक

संख्यांक 10)" जो आज दिनांक 16-4-2001 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

अजय भण्डारी,  
सचिव ।

2001 का विधेयक संख्यांक 10.

## हिमाचल प्रदेश पथकर (संशोधन) विधेयक, 2001

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 (1975 का 9) का संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के वाक्पर्व में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पथकर (संशोधन) अधिनियम, 2001 है ।

संक्षिप्त नाम ।

1975 का 9

2. हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की उद्देशिका में "बैरियर पार करने", शब्दों के स्थान पर "किसी पथ संरचना के ऊपर निकलने", शब्द रखे जायेंगे ।

उद्देशिका का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 में,—

धारा 2 का संशोधन ।

(क) खण्ड (ख) में, "मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 2 के खण्ड (18)", शब्दों, अंकों, चिन्हों और कोष्ठकों के स्थान पर, "मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खण्ड (28)", शब्द, अंक, चिन्ह और कोष्ठक रखे जायेंगे ;

(ख) खण्ड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"(घ-क) "पथ संरचना" से, पथ, सुरंग, फ्लाईओवर, पुल, भूमिगत पथ, पहुँच पथ, नए पथों का कोई भाग या बाह्य पथ जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस रूप में अधिसूचित किया जाए, अभिप्रेत है ;

(घ-ख) "अनुसूची" से, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ग) खण्ड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

(ङ-क) "पथकारी प्राधिकारी" से, राज्य सरकार द्वारा धारा 9-क के प्रयोजन के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति, अभिप्रेत है ;

(ङ-ख) "टोकन" से, अनुसूची के स्तम्भ (4) और (5) में विनिर्दिष्ट दरों पर पथकर संग्रहण का सबूत, अभिप्रेत है ;" ; और

(घ) खण्ड (च) में, "बैरियर पार करने" शब्दों के स्थान पर, "किसी पथ संरचना के ऊपर निकलने", शब्द रखे जायेंगे ।

4. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

धारा 3 का संशोधन ।

(क) उप-धारा (1) में, "बैरियर पार करने" शब्दों के स्थान पर, "किसी पथ संरचना के ऊपर निकलने" तथा शब्दों, कोष्ठकों और अंक "स्तम्भ (3)" के स्थान पर, "क्रमशः स्तम्भ (3), (4) और (5)" शब्द, कोष्ठक, अंक और चिन्ह रखे जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(2) राज्य सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची के स्तम्भ (2) में, यानों की किसी श्रेणी को, जोड़ या हटा सकेगी और इसके स्तम्भ (3), (4) और (5) में विनिर्दिष्ट पथ करों की दर संशोधित कर सकेगी और तदुपरि उपर्युक्त अनुसूची तदनुसार संशोधित हो जाएगी:

परन्तु किसी एक समय पर पथकर की दर, अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर के एक सौ प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी।

(2-क) उप-धारा (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, इसके जारी करने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, विधान सभा के पटल पर रखी जायेगी।”;

(ग) उप-धारा (3) में, “वैरियर पार करने”, शब्दों के स्थान पर, “किसी पथ संरचना के ऊपर निकलने” शब्द रखे जायेंगे;

(घ) उप-धारा (4) में, “चौबीस घण्टे की अवधि के भीतर” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “उस अवधि के भीतर, जिसके लिए पथकर संदत्त किया गया है” शब्द रखे जायेंगे; और

(ङ) उप-धारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धाराएं जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:-

“(5) दैनिक रसीद, चौबीस घण्टे के लिए विधिमान्य होगी और यह अवधि प्रथम वैरियर पार करने से गिनी जाएगी।

(6) त्रैमासिक टोकन, प्रत्येक वर्ष की प्रथम जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर को आरम्भ होने वाले त्रैमास के लिए विधिमान्य होगा।

(7) वार्षिक टोकन, उस वित्तीय वर्ष, जिसके लिए यह जारी किया गया है, के लिए विधिमान्य होगा।”।

धारा 9-क  
का अंत:-  
स्थापन।

5. मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“9-क. चल दस्तों की स्थापना. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, पथकर के संग्रहण को सुनिश्चित करने तथा अपवंचन को रोकने के लिए यातों की चैकिंग हेतु चल दस्तों की स्थापना करने और ऐसे स्थापित चल दस्तों को सरकार के अधिकारी, जो इस अधिनियम के अधीन पथकारी प्राधिकारी होगा, के प्रभावाधीन रखने के लिए आदेश दे सकेगी।

(2) जब पथकारी प्राधिकारी द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, तो यांत्रिक यान का चालक या भार-साधक व्यक्ति, यांत्रिक यान को रोकेंगे और इसे तब तक खड़ा रखेगा जब तक आवश्यक हो, और पथकारी प्राधिकारी को रसीद अथवा संदत्त पथकर के संदाय के टोकन की परीक्षा करने देगा और ऐसे यांत्रिक यान का चालक या भार-साधक व्यक्ति ऐसी अन्य जानकारी भी देगा जैसी पथकारी प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो।

(3) यांत्रिक यान का चालक या भार-साधक व्यक्ति, हिमाचल प्रदेश राज्य के परिक्षेत्र में अन्तिम प्रवेश के कम से कम 72 घण्टे तक पथकर के संदाय की रसीद तथा टोकन को इसके अवमान के पन्द्रह दिन तक यान में रखेगा और पथकारी प्राधिकारी के मांगने पर इसे प्रस्तुत करेगा।

(4) यदि यांत्रिक यान का चालक या भार-साधक व्यक्ति, उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित टोकन या पथकर के संदाय की रसीद को पेश करने में असफल रहता है, तब पथकारी प्राधिकारी, अनुसूची के स्तम्भ (3) के अधीन विनिर्दिष्ट दर पर निरीक्षण के स्थान पर, पथकर को वसूल करेगा :

परन्तु पथकर प्राधिकारी, पथकर के अतिरिक्त, अनुसूची के स्तम्भ (3) के अधीन विनिर्दिष्ट दर के चार गुना के बराबर की संग्रहण फीस वसूल करेगा।

(5) उप-धारा (4) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने हुए भी, पथकारी प्राधिकारी, यांत्रिक यान को, उसमें ले जाए जा रहे माल, यदि कोई हो, सहित ऐसी अवधि के लिए, जो युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो, निरुद्ध करने का आदेश दे सकेगा और यांत्रिक यान का चालक या भार-साधक व्यक्ति, इस धारा के अधीन अधिरोपित पथकर तथा फीस के संग्रहण की रकम का संदाय करने या उसके समाधानप्रद रूप में प्रतिभूति प्रस्तुत करने या पथकर और संग्रहण फीस की रकम की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रतिभूति के साथ या बिना वन्धपत्र निष्पादित करने पर ही उसे जाने की अनुज्ञा देगा।”।

6. मूल अधिनियम की धारा 13 में, “यांत्रिक यानों” शब्दों के पश्चात् और “को लागू नहीं होगी” शब्दों से पूर्व, “फायर टैंडर, ऐम्बुलैन्स और विकलांग व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया जाने वाला विशेष रूप से डिजाईन यान” शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

धारा 13 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

अनुसूची का प्रतिस्थापन।

### “अनुसूची

(धारा-3 देखें)

क्रम सं०	यानों की विशिष्टियां	प्रतिदिन या उसके भाग के पथकर की दर	प्रति त्रिमास या उसके भाग के पथकर की दर	प्रतिवर्ष या उसके भाग के पथकर की दर
1	2	3	4	5

1. यान की लड़ाई की क्षमता :

(क) नब्बे किंवदल से अधिक	50 रुपये	स्तम्भ 3 में यथा विनिर्दिष्ट दरों का बीस गुणा।	स्तम्भ 4 में यथा विनिर्दिष्ट रकम का तीन गुणा।
--------------------------	----------	--	---

1	2	3	4	5
	(ख) 20 से अधिक किन्तु 90 किबटल तक।	40 रुपये	-यथोपरि-	-यथोपरि-
	(ग) 10 से अधिक किन्तु 20 किबटल तक।	30 रुपये	-यथोपरि-	-यथोपरि-
	(घ) सार्वजनिक वाहक या निजी वाहक परमिट से चलाये जा रहे ट्रैक्टर।	30 रुपये	-यथोपरि-	-यथोपरि-
2. याली यान में बैठने की क्षमता :				
	(क) बारह यात्रियों से अधिक	50 रुपये	-यथोपरि-	-यथोपरि-
	(ख) बारह यात्रियों तक	25 रुपये	-यथोपरि-	-यथोपरि-
	(ग) अन्य हल्के मोटर यान जैसे जीप, कार, पिक-अप-वैन, स्टेशन वैन :			
	(i) निजी यान के रूप में रजिस्ट्रीकृत	20 रुपये	-यथोपरि-	-यथोपरि-
	(ii) सार्वजनिक वाहक के रूप में रजिस्ट्रीकृत	30 रुपये	-यथोपरि-	-यथोपरि-
3.	(क) मोटर रिक्शा और स्कूटर रिक्शा	10 रुपये	-यथोपरि-	-यथोपरि-
	(ख) मोटर साइकिल और स्कूटर	5 रुपये	-यथोपरि-	-यथोपरि-

नोट.—(i) स्तम्भ (3) के अंगीन विनिर्दिष्ट दर के संदाय पर, रसीद जारी की जायेगी।

(ii) स्तम्भ (4) और (5) के अंगीन विनिर्दिष्ट दरों के संदाय पर, अधिसूचित डिजाईन में एक टोकन जारी किया जायेगा और इसे यान पर प्रदर्शित किया जा सकेगा।”

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

अभी तक सड़क उपभोक्ताओं को कई बैरियरों पर पथकर देने के लिए रुकना पड़ता था जोकि सरकार एवं स्थानीय निकायों द्वारा संप्रहीत किया जा रहा था। बैरियरों की अधिसंख्या मनुष्यों एवं सामान के स्वतंत्र आवागमन में बाधा डाल रही थी। यह प्रतिकूल प्रचार उत्पन्न करते हुए राज्य के पर्यटन उद्योग के विकास में भी अड़चन डाल रही थी। राज्य में स्वतन्त्र एवं अवरोध मुक्त सड़क परिवहन सुविधा देने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि पथकर का संग्रहण राज्य के अधिमूर्चित परिसीमित स्थानों पर किया जाए। इसके अतिरिक्त, यह भी अनिवार्य समझा गया है कि 25 वर्ष पूर्व निर्धारित पथकर दरों में संशोधन किया जाए। अतः हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 में संशोधन करना अपेक्षित है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रेम कुमार धूमल,  
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

.....2001.

## वित्तीय ज्ञापन

यह विधेयक पथकर की दरें बढ़ाने के लिए है। इस पथकर को बढ़ाने से राजकोष में लगभग 20 करोड़ पए की वार्षिक आय होनी संभाव्य है। विधेयक अधिनियमित किये जाने पर प्रशासनिक तंत्र द्वारा प्रशासित किया जायेगा और इससे राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

## प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड-4, राज्य सरकार को, अनुसूची से यानों की किसी श्रेणी को जोड़ने या हटा सकने तथा अनुसूची में विनिर्दिष्ट पथकर की दरों को संशोधित करने के लिए सशक्त करता है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

## भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[नस्ति संख्या पी0बी0 डब्ल्यू0 (बी0 एण्ड आर0) बी0 (1) 1-1/2001]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पथकर (संशोधन) विधेयक, 2001 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उपर्युक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

---

**हिमाचल प्रदेश पथकर (संशोधन) विधेयक, 2001**

हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 (1975 का 9) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

प्रेम कुमार धूमल,  
मुख्य मन्त्री।

रामेश्वर शर्मा,  
सचिव (विधि)

शिमला:

..... 2001.



**AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT**

**Bill No. 10 of 2001.**

**THE HIMACHAL PRADESH TOLLS (AMENDMENT) BILL, 2001**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

**A**

**BILL**

*to amend the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975 (Act No. 9 of 1975).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-second Year of the Republic of India, as follows :—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Tolls (Amendment) Act, 2001.

Short title.

9 of 1975

2. In Preamble of the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975 (hereinafter referred to as the "principal Act"), for the words "crossing barriers", the words "passing over any road infrastructure" shall be substituted.

Amendment of Preamble.

3. In section 2 of the principal Act,—

Amendment of section 2.

(a) in clause (b), for the brackets, figures, words and sign "(18) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939)", the brackets, figures, words and sign "(28) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988)" shall be substituted;

(b) after clause (d), the following shall be added, namely :—

"(d-a) "road infrastructure" means roads, tunnels, flyovers, bridges, underground roads, approach roads, any section of new roads or bye-passes which may, from time to time, be notified as such by the State Government ;

(d-b) "Schedule" means Schedule appended to this Act ;";

(c) after clause (e), the following shall be added, namely :—

"(e-a) "tolling authority" means any person appointed by the State Government for the purpose of section 9-A;

(e-b) "token" means proof of collection of toll at the rates specified in columns (4) and (5) of the Schedule ;"; and

(d) in clause (f), for the words "crossing a barrier", the words "passing over any road infrastructure" shall be substituted.

4. In section 3 of the principal Act,—

Amendment of section 3.

(a) in sub-section (1), for the words "crossing a barrier", the words "passing over any road infrastructure" and for the words,

bracket and figure "column (3)", the words, brackets, figures and sign "columns (3), (4) and (5)" respectively shall be substituted ;

(b) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely :—

"(2) The State Government may subject to the condition of previous publication, by notification add to or delete any class of vehicles from column (2) of the Schedule and amend the rate of tolls specified in columns (3), (4) and (5) thereof and thereupon the said Schedule shall stand amended accordingly :

Provided that the rate of toll shall not be increased at any one time by more than 100% of the rate specified in the Schedule.

(2-A) Every notification issued under sub-section (2) shall, as soon as may be, after it is issued, be laid on the Table of the Legislative Assembly." ;

(c) in sub-section (3), for the words "crossing a barrier", the words "passing over any road infrastructure" shall be substituted ;

(d) in sub-section (4), for the words and figure "within the period of 24 hours", the words "within the period for which the toll is paid" shall be substituted ; and

(e) after sub-section (4), the following sub-sections shall be added, namely :—

"(5) Daily receipt shall be valid for 24 hours and the period shall be counted from crossing the first barrier.

(6) Quarterly token shall be valid for the quarter beginning with the 1st of January, April, July and October of each year.

(7) The annual token shall be valid for the financial year for which it is issued."

Insertion of section 9-A. 5. After section 9 of the principal Act, the following shall be inserted, namely :—

"9-A. *Establishment of Mobile Squads.*—

(1) The State Government may, by notification, order the establishment of Mobile Squads for checking of the vehicles to ensure collection of the toll and prevent evasion and the Mobile Squads so established shall be under the charge of an officer of the Government who shall be a tolling authority under this Act.

(2) When so required by the tolling authority, the driver or the person-in-charge of the mechanical vehicle shall stop the mechanical vehicle and keep it stationary as long as may be necessary, and allow the tolling authority to examine receipt or token of payment of toll paid and the driver or the person-in-charge of such mechanical vehicle shall also furnish such other information as may be required by the tolling authority.

(3) The driver or person-in-charge of the mechanical vehicle shall keep in the vehicle the receipt of payment of toll at least upto 72 hours of last entry into the territory of the State of Himachal Pradesh and the token upto 15 days of its expiry, and on demand shall produce it to the tolling authority .

(4) If the driver or the person-in-charge of the mechanical vehicle fails to produce the receipt of payment of toll or token, as required under sub-section (3), then the tolling authority shall recover the toll at the place of inspection at the rate specified under column (3) of the Schedule :

Provided that in addition to the toll, the tolling authority shall recover a collection fee of equal to 4 times the rates specified under column (3) of the Schedule.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (4), the tolling authority may also order detention of the mechanical vehicle, including the goods, if any, being carried therein, for such period as may reasonably be necessary and shall allow the same to proceed only after the driver or the person-in-charge of the mechanical vehicle making payment of the toll and the amount of collection fee imposed under this section or furnishing to his satisfaction a security or executing a bond with or without sureties for securing the amount of toll and collection fee.”.

6. At the end of section 13 of the principal Act, the words and sign “Fire tenders, Ambulances and vehicle specially designed for use by physically handicapped person”, shall be added.

Amendment of section 13.

7. For the Schedule of the principal Act, the following shall be substituted, namely :—

Substitution of the Schedule.

### “SCHEDULE

(See section-3)

Sr. No.	Particulars of vehicles	Rate of toll per day or part thereof	Rate of toll per quarter or part thereof	Rate of toll per year or part thereof
1	2	3	4	5
1.	Vehicle having load- ing capacity :			
	(a) Exceeding 90 quintals.	Rs. 50.00	20 times the rate as speci- fied in Column (3)	3 times the amount as specified in Column (4)

1	2	3	4	5
	(b) Exceeding 20 but upto 90 quintals.	Rs. 40.00	-do-	-do-
	(c) Exceeding 10 but upto 20 quintals.	Rs. 30.00	-do-	-do-
	(d) Tractors plying with public carrier or private carrier permit.	Rs. 30.00	-do-	-do-
2.	Passenger vehicles having seating capacity of :			
	(a) above 12 passengers	Rs. 50.00	-do-	-do-
	(b) upto 12 passengers	Rs. 25.00	-do-	-do-
	(c) other light motor vehicles such as jeep, car, pick-up van, station wagon :			
	(i) Registered as Private Vehicle.	Rs. 20.00	-do-	-do-
	(ii) Registered as public carrier.	Rs. 30.00	-do-	-do-
3.	(a) Motor Rickshaw and Scooter Richshaw.	Rs. 10.00	-do-	-do-
	(b) Motor Cycles and Scooters.	Rs. 5.00	-do-	-do-

*Note.*—(i) For payment at rate specified under column (3) a receipt will be issued.

(ii) For payments at rates specified under columns (4) and (5) a token in notified design will be issued and it shall be displayed on the vehicle.”.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Till recently, road users had to stop at a number of barriers to pay toll that was being collected by Government and Local Bodies. The multiplicity of barriers was hindering free movement of men and materials. This was also generating adverse publicity and impeding the growth of Tourism Industry in the State. To facilitate free and obstruction free road transport in the State, it has been decided to collect tolls at limited notified points in the State. In addition to this it has been considered necessary to revise the rate of toll fixed 25 years back. This has necessitated the amendment in the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

PREM KUMAR DHUMAL,  
*Chief Minister.*

SHIMLA :

The .....2001.

## FINANCIAL MEMORANDUM

The Bill seeks to enhance the rates of toll fixed 25 years ago. This enhancement of toll is likely to yield about 20 crores annually to the State Exchequer. The provisions of the Bill when enacted will be administered by the existing administrative machinery and will not result in additional expenditure from the State Exchequer.

## MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 4 of the Bill empowers the State Government to add to or delete from any class of vehicles from the Schedule and also to amend the rates of toll specified in the Schedule. The proposed delegation of powers is essential and normal in character.

## RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[File No. PBW (B & R) B (1)1-1/2001]

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Tolls (Amendment) Bill, 2001, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the said Bill in the Legislative Assembly.

---

**THE HIMACHAL PRADESH TOLLS (AMENDMENT) BILL, 2001****A****BILL***to amend the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975 (Act No. 9 of 1975)***PREM KUMAR DHUMAL**  
*Chief Minister.***RAMESHWAR SHARMA,**  
*Secretary (Law).***SHIMLA :**  
*The ..... 2001.*